

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/677

भोपाल, दिनांक/8-2-25

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 08.07.2024

-----0-----

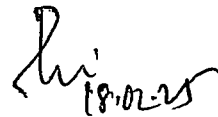
कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका पालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व दिनांक 18.02.2025 से यह आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उल्लंघन से संबंधित शर्तें वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लगाई गई हैं, इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जावे।

अतः प्रकरण में भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/334 दिनांक 24.01.2025 से भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को भेजे गए पालन प्रतिवेदन की 01 प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें, ताकि रेलवे विभाग को क्षेत्र हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/678

भोपाल, दिनांक 18-2-25

प्रतिलिपि:-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
 3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
 4. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा
- की ओर संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/ 154962/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 08.07.2024

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

- 1- शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2- शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा उल्लंघन की Penalty for violation five times NPV राशि रु 2,15,50,050/- ऑनलाईन दिनांक 18.09.2024 से कैम्पा मद में जमा कराई जा चुकी है।
- 3- शर्त क्रमांक (3) के पालन में भारत सरकार द्वारा लेख किया गया है कि धारा 3ए एवं 3बी के तहत कार्यवाही शुरू करेगा। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 जैसा लागू हो कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है। इस संबंध में प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र दिनांक 01.04.2024 से प्रेषित किया गया है कि "छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन 6.654 हेक्टेयर अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारणवश कलेक्टर जिला अलीराजपुर द्वारा वर्ष 2018 में भूमि अधिग्रहण कर रेलवे विभाग को हस्तांतरित की गई थी। उक्त भूमि संरक्षित वन घोषित करने के बाद राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन नहीं किया गया था। जिस कारण से आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर निर्माण कार्य किया गया है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन रोकने में असमर्थ रहने के संबंध में वन मण्डल अधिकारी अलीराजपुर द्वारा दोषी पाये गये वन अधिकारियों/कर्मचारियों को लघुशास्ति परिनिन्दा से दण्डित किया गया है।"

4- शर्त क्रमांक (4) के पालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.12.2024 में दिए निर्देशानुसार दुग्ने बिगड़े वनक्षेत्र की रोपण योजना पूर्व से ही पोर्टल में अपलोड है।

5- शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

6- शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया है कि "There is only one railway station named "jamaniya" in the forest land under the jurisdiction DFO/Dhar, which comes under compartment number 81 & 82 of Tanda forest range and the required area for jamaniya station is 18.31 ha and the rest 225.728 ha area will be used for Railway line work."

7- शर्त क्रमांक (7) के पालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.12.2024 में दिए निर्देशानुसार दुग्ने बिगड़े वनक्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की लागत राशि रुपये 23,69,80,275/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 16.01.2025 से ऑनलाईन कैम्पा में जमा कराई गई है।

8- शर्त क्रमांक (8) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 23,37,35,673/- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दि. 18.09.2024 को जमा की जा चुकी है।

9- शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

10- शर्त क्रमांक (10) के पालन में आवेदक संस्था सहमत है, वचन पत्र दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

11- शर्त क्रमांक (11) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा सहमत है।

12- शर्त क्रमांक (12) के पालन में आवेदक संस्था ने अपने पालन प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि no reclamation of any quarry is involved in this Project.

13- शर्त क्रमांक (13) से (15) के पालन में आवेदक संस्था सहमत है।

14- शर्त क्रमांक (16) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर धार एवं अलीराजपुर का प्रमाण पत्र क्रमशः दिनांक 23.01.2025 एवं 25.09.2024 से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

15- शर्त क्रमांक (17) के पालन में ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 54795 है।

16- शर्त क्रमांक (18) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि दि. 16.01.2025 को एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू एवं उल्लंघन की दाण्डिक राशि दिनांक 18.09.2024 को एड-हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।

17— शर्त क्रमांक (19) के पालन में भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.12.2024 में दिए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

18— शर्त क्रमांक (20) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा पेड़ों की कटाई की राशि आवेदक संस्थान से वसूल की जावेगी। इस संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

19 — शर्त क्रमांक (21) एवं (22) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

20— शर्त क्रमांक (23) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि किसी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। इस संबंध में वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो हार्डकॉपी में संलग्न है।

21 — शर्त क्रमांक (24) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अपने पालन प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

22 — शर्त क्रमांक (25) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है, वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो हार्डकॉपी में संलग्न है।

23 — शर्त क्रमांक (26) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

24 — शर्त क्रमांक (27) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि रेल्वे सीमा को पहले से ही साइड पर चिह्नित किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद रेल्वे फिर से सीमांकन करेगा।

25 — शर्त क्रमांक (28) से (33) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

26— शर्त क्रमांक (34) तक के पालन संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा इसका शर्त का पालन सुनिश्चित करेंगे।

27 — शर्त क्रमांक (35) से (38) तक के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

28— शर्त क्रमांक (39) तक के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा पालन प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

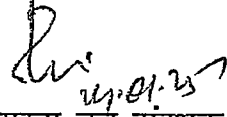


(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/ 335
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

1. सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003
 2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
 3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
 4. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा
- की ओर संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार (अनु क्र.-1 हेतु)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Western Railway



Ankit kumar, IRSE
Deputy Chief Engineer/C/III.
Mob. No. +91-9724091253

Office of the,
Dy. Chief Engineer(Const.)III,
Pratapnagar, Vadodara-04
Email.dycec3brc@gmail.com

No. BRC/W/115/27 (Forest)

Date: 23.01.2025

To,
Additional Principal Chief Conservator of Forest [Land Management]
Van Bhavan,
Madhya Pradesh
Bhopal - 462003

[Kind attention: H. S. Mohanta]

Sub: Proposal for diversion of forest land 244.039Hec. for construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar. (Proposal No. FP/MPRAIL/154962/2022)

Ref: 1. Your letter number क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/3586, भोपाल, दिनांक 9-7-24
2. Letter of Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, dated 08.07.2024

Sir,

Apropos above, in respect of observations of MOEF letter on dated 08.07.2024 the para wise remarks of this office are as under.

S. No.	OBSERVATIONS	COMPLIANCE
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	Noted. Undertaking is given here with that legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
2	The penalty for violation shall be five times the NPV for the area used in violation plus 12% simple interest from the date of raising of such demand till the deposit is made.	This item has already been complied in Sept. 2024. Railway has already deposited a sum total of Rs. 25,52,85,723/- in Madhya Pradesh CAMPA Fund Account No. 1507659154962996 on 18.09.2024 through RTGS against e-challan no. 59154962996, dated 03.09.2024, generated by APCCF/L&M/Bhopal, which had included a penal amount of Rs. 2,15,50,050/- towards penalty for violation, as per the demand letter of DFO/Alirajpur and a sum total of Rs. 23,37,35,673/- towards payment of NPV for the entire proposed diversion of 244.039 ha, as per the

Handwritten signature and date 24/1/25

Handwritten signature

		<p>subject proposal, which includes diversion of 237.385 Ha reserved forest land in the jurisdiction of DFO/Dhar and 6.654 Ha under DFO/Alirajpur.</p> <p>In supporting documentary evidence of above, a copy of printout of the statement of "Funds to be deposited in Govt. Exchequer" as taken from "Parivesh Portal" in connection with subject proposal FP/MP/RAIL/154962/2022 and in specific reference of aforesaid challan is submitted here with as Annexure-A.</p>
3	<p>The state shall initiate action under section 3A and /or 3B of van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation.</p>	<p>Compliance of this item pertains to MP State Forest Department.</p>
4	<p>As per the provisions contained in the Van (sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2003, the compensatory Afforestation cannot be allowed on degraded forest land in the instant case. The state shall therefore identify alternative land for CA as per the provisions of extant Rules. The said land shall be transferred and mutated in the name of the forest department and notified as protected forest under the provisions of Indian Forest Act, 1927 or the State specific laws.</p>	<p>This item has since been complied with.</p> <p>In terms of MOEFs letter, dated 17.12.2024 and subsequent demand letters, received from DFO/Alirajpur and DFO/Dhar, a sum total of Rs. 23,69,80,275/- towards "Compensatory Afforestation", which includes Rs. 86,58,181/- under DFO/Alirajpur and Rs. 22,83,22,094/- under DFO/Dhar for the total area of 494 Ha (i.e. 2 times the total area of 244.039 Ha), has since been deposited in Madhya Pradesh CAMPA Funds account no. 1507659154962058, on 15.01.2025 through RTGS.</p> <p>In supporting documentary evidence of above, a copy of printout of the statement of "Funds to be deposited in Govt. Exchequer" as taken from "Parivesh Portal" in connection with subject proposal FP/MP/RAIL/154962/2022 and in specific reference of aforesaid challan is submitted here with as Annexure-A</p> <p>In addition to above, demanded supervision charges @10% on CA cost has also been deposited online in MP Treasury Challans (Annexure-B).</p>
5	<p>Detailed Animal Passage and mitigation plan shall be prepared in consultation with the Chief wildlife warden and the same shall be implemented at the cost of the user agency.</p>	<p>There is no such wild life requiring any animal passage/mitigation plan. However, if MP State Forest Department advises some requirement in consultation with Chief Wildlife Warden, the same will be provided by Railway at its cost.</p> <p>Undertaking Enclosed in Annexure I.</p>
6	<p>The state shall submit the detailed bifurcation of the area involved in the Railway Station and Railway line. A certificate that only 244.039 ha area is</p>	<p>There is only one railway station named "Jamniya" in the forest land under the jurisdiction DFO/Dhar, which comes under compartment number 81 & 82 of Tanda forest range, and the</p>

	required for the project shall also be submitted.	required area for Jamniya station is 18.311 ha and the rest 225.728 ha area will be used for Railway line work.
7	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	This item has since been complied with as per details given in reply of item no. 4.
8	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the guidelines in the matter.	This item has already been complied with in entirety as per details given in reply of item no. 2 above, read with documentary evidence at Annexure-A.
9	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.	Yes, Railway agree to pay as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India. Undertaking Enclosed in Annexure II
10	The State Government shall ensure controlled speed limit if the trains passing through the forest portion to enable the trains drivers to react to the sudden appearance of the wild animals on the track. As and when required speed of train shall be regulated in consultation with Chief Wildlife Warden of the State Government.	This item pertains to State Forest Department. Undertaking is given here with, that necessary speed restriction, as and when advised by State Government, will be imposed by Railway. Undertaking Enclosed in Annexure III
11	The designing of culverts/bridges. If any, over the natural streams/rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.	Yes, Railway will build the bridges keeping this in mind, due to which there will be no hindrance in the flow of water or the movement of wild animals.
12	The reclamation of quarry, if any, should be done under the supervision of the State Forest Department. The quarry shall be reclaimed and afforested completely before the project is closed.	This items pertains to State Forest Department. However, no reclamation of any quarry is involved in this project.

13	The user agency will provide retaining walls, breast walls and drainage as per requirement to make the slope stable.	Yes, Railway will provide retaining wall, toe wall and drainages as per requirement to make the slope stable.
14	The user agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the state forest department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report.	Yes, Railway is agree to comprehensive soil conservation measures in the diverted area as per requirement and consultation of state forest department.
15	If required, provision for construction of sufficient underpasses for safe crossing of animal shall be made in consultation with Chief Wildlife Warden.	Yes, Railway is agree to construct more underpasses for safe crossing of animal as per requirement of Chief Wildlife Warden, also Railway is already proposed 149 number of bridges in diverted forest area for Stream line crossing, Nala Crossing, Road crossing and Balancing culvert which are also helpful for the passage of animal and the average distance between two bridges is 400m to 500m.
16	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA certificate for Alirajpur district is attached, also it is undertake that the Certificate against Schedule Tribe (ST) and other Traditional Forest Dwellers (OTFD) recognition of Forest Right Act, 2006, will be submitted on receipt of the same for Dhar district from the concerned District Magistrate & Collector in connection with "Proposal for diversion of forest land 237.385 ha Dhar Alirajpur Forest Division for construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar. Getting FRA Certificate from Collector Dhar is under progress.
17	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the E-green watch portal of FSI, before handing over forest land to the user agency.	Pertains to DFO office Alirajpur and Dhar.
18	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through e-portal (http://parivesh.nic.in/); Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.	Yes, Railway has already deposited the requisite amounts in CAMPA account as per generated CHALAN through e-portal (http://parivesh.nic.in/). No other mode has been adopted. Supervision charges @10% on Compensatory Afforestation Cost has also been deposited online in MP Treasury fund.
19	Forest land will be handed over only after required non-forest land in the project is obtained by the user agency.	This item is not applicable now. As per the MOEF's letter dated 17.12.2024 and demands of MP State Forest Department, requisite amount for two times of the area under diversion has since been deposited by Railway to MP CAMPA fund along with 10% supervision charges in MP Treasury Challan (Annexure-A & B).

20	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Noted. Railway is agreed to deposit the cost of felling of trees in the State Forest Department. Undertaking Enclosed in Annexure IV
21	The User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land and trees shall be felled under strict supervision of the State Forest Department.	Noted. Undertaking for compliance by Railway is given here with.
22	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
23	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.	The R&R Plan will be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. Monitoring will be done by DFO office Alirajpur and Dhar. Undertaking Enclosed in Annexure V
24	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	Environment Clearance is not required for this project, as this project does not impact the environment, public health or other protected areas. This project will provide rail link in between Vadodara and Indore which will improve the connectivity in between the cities in the golden quadrilateral and central India. This will also give locals people, living in the vicinity of this railway line, to visit nearby bigger cities and easily gain from the opportunities available in big cities.
25	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir.	Railway has since paid the afforestation amount as per demand letter's received from State government through e-portal (http://parivesh.nic.in/). CA area is already verified by Dy.DG sir, MOEF on dated.12 th and 13 th September 2023. Undertaking Enclosed in Annexure VI
26	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
27	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete	Railway boundary post is already marked at site with its Chainage and GPS coordinates are verified and submit through ranger letter no. कमांक/मा.चि. /2023/316 टाण्डा, दिनांक : 03/03/2023 and कमांक/480

	pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.	सरदारपुर/दिनांक/9/3/23, again after completion of construction work, Railway will demarcate the land boundary in a proper manner as per GPS coordinate.
28	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.	Yes, Railway will not transfer the proposed diverted forest land to any other agency, department or person.
29	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
30	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
31	No additional or new path will be constructed inside the forest area for the execution of this project.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
32	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
33	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
34	The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary mitigative measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.	Pertains to DFO office Alirajpur and Dhar.
35	The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Integrated Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
36	The user agency shall comply all provisions of the all Acts, rules, regulations, guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
37	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.

38	Violation of any these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry on dated 29.12.2023.	Noted. Undertaking is given here with for compliance.
39	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.niv.in/).	Compliance report with all necessary attachment will be uploaded on e-portal (https://parivesh.niv.in/).

It is requested to issue the Working Permission.

D.A as above.

Your's sincerely,

**Dy. Chief Engineer (Construction)III,
Western Railway, Vadodara-390 004**

Copy to.

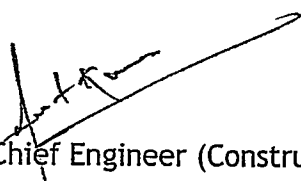
1. DFO/Dhar for necessary action please.
2. DFO/Alirajpur for necessary action please.

UNDERTAKING

Animal Passage Plan १७३०-५

I , by virtue of power delegated to me by New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway, govt of India that:

"If the Animal passage plan required we submitted same in your office. However we have proposed 143 Culverts and Bridges for passing animal and natural drain in forest area is involved in the proposal submitted for diversion of 244.039 ha of Forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project.


Dy. Chief Engineer (Construction)III,
Western Railway,Vadodara-390004

UNDERTAKING

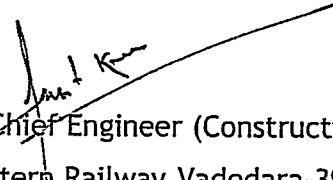
१७/५/०९

To pay additional Charges towards NPV (Net Present Value) as per directions of
Honorable Supreme Court

I, by virtue of power delegated to me by construction of New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway Govt. Of India that:

All the terms and conditions imposed by the MoEF& CC / Government of India / Dept of Forest / Government of Madhya Pradesh , under the relevant Act and the rules, in connection with our application for Diversion of 244.039 ha forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project in Alirajpur / Dhar district (Madhya Pradesh) will be duly abided by the Railways, Govt of India.

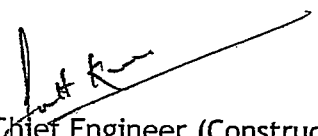
1. Railway shall also pay the additional charges (if any) as per the directions of Honourable Supreme Court of India towards the NPV (Net Present Value)


Dy. Chief Engineer (Construction) III,
Western Railway, Vadodara-390004

UNDERTAKING २१२५० १०
Take Measures for Speed restriction

I , by virtue of power delegated to me by New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar,, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway, Govt of India that:

"The necessary speed restriction, as and when advise or suggested by authority, railway take measures regarding the same in forest area is involved in the proposal submitted for diversion of 244.039 ha of Forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project.


Dy. Chief Engineer (Construction)III,
Western Railway,Vadodara-390004

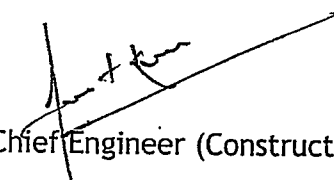
UNDERTAKING

स.स.स. २०

Deposit Cost of felling Trees

I , by virtue of power delegated to me by New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar,, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway, Govt of India that:

"The railway deposit to cost of felling of trees to forest department in forest area is involved in the proposal submitted for diversion of 244.039 ha of Forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project.


Dy. Chief Engineer (Construction) III,
Western Railway, Vadodara-390004

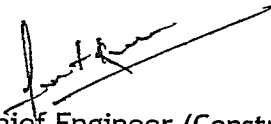
UNDERTAKING

Deposit R&R PLAN

१९८०२३

I , by virtue of power delegated to me by New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar,, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway, Govt of India that:

"There is no resettlement and rehabilitation plan involve in this in forest area is involved in the proposal submitted for diversion of 244.039 ha of Forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project.

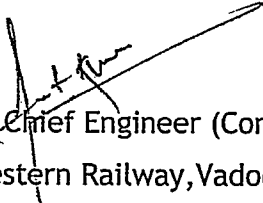

Dy. Chief Engineer (Construction)III,
Western Railway,Vadodara-390004

UNDERTAKING 37/2 3025

For Afforestation along the periphery of the reservoir

I, by virtue of power delegated to me by New Railway Broad Gauge line between Chhotaudepur to Dhar, do hereby affirm and undertake on behalf of the Railway, Govt of India that:

"The afforestation has been along the periphery of the reservoir in forest area is involved in the proposal submitted for diversion of 244.039 ha of Forest land for Under Rail Line Village Kakdwa, Barad, Tanda, Jamli, Amniyapada, Khandala, Ganganagar, Sultanpura, Jhiknyabardi, Matlabpura, Bawadikhodra, Malgarh, Chuliya, Degaon of Chhotaudepur to Dhar new gauge conversion rail line project.


Dy. Chief Engineer (Construction) III,
Western Railway, Vadodara-390004

Form-1
(For linear projects)
(Government of India)
(Office of the Collectorate Distt. Dhar)

No. 840

Dated 23/01/2025


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

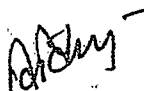
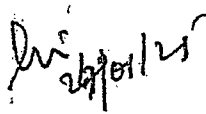
In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC dated 3 rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition for Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, read with MOEF's letter Dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 237.385 hectares of forest land propose to be diverted in favour of Western railway for Construction of New BG Railway line between Chhotaudepur to Dhar section in Dhar District.
It is further certified that.

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 237.385 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee(s) are enclosed as Annexure 1 to 4 Annexure
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl :- As above

(Approved by DLC)


(Priyank Mishra)
Collector
District Dhar M.P.

Annexure 1 FORM-1
(For Linear projects)
Government of India (Ministry of Environment & Forest)
Office of the District Collector, Alirajpur

NO. 452/Reader/2024

Dated 25/09/2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11/09/98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines. On submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other traditional Forest dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the Forest, land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that land will be 6.654 hectares & in favor of Western railway for CTD-DHAR New line project.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.67 Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure. 1 to 4 annexure-04
- b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agriculture communities.

Encl..As above

(Dr. Abhay Arvind Bedekar)
Collector
Alirajpur (M.P.)
District Alirajpur (M.P.)

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
 Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
 Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made. Paid : This icon shows that the payment has been made.

⊙Proposals received on or after 15th July 2014 ○All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

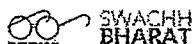
Select User Agency :

Payment Status : ☐ Paid ☐ Unpaid ☒ All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/RAIL/154962/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/RAIL/154962/2022) Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	RAIL154962202205808	08 Jul 2024	CA: 236980275/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/- Total : 236980275/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 26 Dec 2024 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 27 Dec 2024 Transaction Date 16 Jan 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/261220241448072473_FPMRAIL1549622022_) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RAIL1549622022_)
2	FP/MP/RAIL/154962/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/RAIL/154962/2022) Chhotaudepur to Dhar New Broad Gauge railway line project	RAIL154962202205808	08 Jul 2024	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 233735673/-For Violation Penalty 21550050/- Total : 255285723/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 29 Aug 2024 Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 03 Sep 2024 Transaction Date 18 Sep 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/280820241305502703_FPMRAIL1549622022_) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=RAIL1549622022_)



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



MeitY

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilltystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:54795

Project Name : **Chhotaudepur to
Dhar New Broad
Gauge railway line
project**

Year : **2024**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.